

मुकदमों का विवरण

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम

पी. जादेन्गा

(सिविल अपील सं. 2012 की 2518) अक्टूबर 03, 2023

[ऋषिकेश रॉय और संजय करोल, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या 10 अप्रैल 2002 के समझौता ज्ञापन (एम. ओ. एस.) का खंड 4 विभागीय कार्यवाहियों को जारी रखने पर रोक लगाता है जब उसके अधीन व्यक्ति पर उसी मूल के अपराधों के लिए आपराधिक न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जा रहा है और क्या कुछ संबंधित कार्यवाहियों में बरी होने से बची हुई कार्यवाहियों में लाभ होता है, जिससे अपराधी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में स्वचालित निर्वहन का अधिकार मिलता है।

सेवा विधि -समान लेन-देन से उत्पन्न आपराधिक मुकदमे के लंबित विभागीय कार्यवाही, यदि रोक लगाई जानी है-एक कार्यवाही में बरी होना यदि दूसरे में बरी होना आवश्यक है:

आयोजित किया गया: एम. ओ. एस. का खंड 4 आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के परिणामस्वरूप विभागीय कार्यवाही के पूर्ण ठहराव की परिकल्पना नहीं करता है-यह वांछनीय हो सकता है या, कुछ परिस्थितियों में, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए रोक लगाने की सलाह दी जा सकती है जब आपराधिक कार्यवाही चल रही हो, हालांकि, रोक "निश्चित रूप से एक मामला" नहीं है और केवल सभी कारकों पर विचार करने के बाद दी जानी है, इसके पक्ष और विपक्ष में-विभागीय कार्यवाही को अनुचित और अन्यायपूर्ण रूप से विलंबित नहीं किया जा सकता है-अनुशासनात्मक कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही प्रतिवादी कार्रवाई को चुनौती देने वाली एम. ओ. एस. एफ. आई. के नेतृत्व वाली रिट याचिका के खंड 4 पर भरोसा करता है, जो केवल इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए एक विलंबित प्रयास था-इसके अलावा, मुकदमे के पूरा होने को "उचित समय के भीतर पूरा" माना जाना चाहिए।

740

741

कहीं भी पूरा होने के करीब नहीं है-तथ्यों पर, एम. ओ. एस. की कोई याचिका कभी भी पूरी नहीं की गई थी-आपराधिक निर्णय के समापन की प्रतीक्षा में अनुशासनात्मक कार्यवाही को आक्षेपित करने की कोई विशिष्ट याचिका नहीं की गई थी-न ही यह मामला था कि जिस निर्णय के अधीन प्रतिवादी को अपराध करने के एक वर्ष के भीतर शुरू किया गया था और न ही रिकॉर्ड इस आशय से बात करता है-अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना अनिवार्य नहीं है, विशेष रूप

से जब वे एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद शुरू की गई थी-खंड 4 के भीतर प्रतिबंध पूर्ण नहीं है और तथ्यों पर लागू किया जाना है-इसके अलावा, कार्यवाही की प्रकृति पूरी तरह से अलग और विशिष्ट है, आपराधिक कार्यवाही में बरी होने से अपराधी कर्मचारी को बाद में किसी भी लाभ के लिए या विभागीय में स्वचालित निर्वहन का अधिकार नहीं है।[पैरा 14.2,15,19,22-24,26 और 28-30]

सेवा विधि -एक साथ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही, उनसे निपटने के लिए सिद्धांत-चर्चा की गई।

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम नीलम नाग (2016) 9 एससीसी 491:[2016] 5 एससीआर 278; राजस्थान राज्य बनाम बी. के. मीना और अन्य। (1996) 6 एससीसी 417:[1996] 7 पूरक।एस. सी. आर. 68; एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (1999) 3 एस. सी. सी. 679:[1999] 2 एस. सी. आर. 257; कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड वी.सी. नागराजू (2019) 10 एस. सी. सी. 367; नेल्सन मोटीस बनाम भारत संघ (1992)

4 एससीसी 711:[1992] 1 पूरक।एस. सी. आर. 325; कर्नाटक राज्य बनाम उमेश (2022) 6 एस. सी. सी. 563-पर निर्भर।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एंड ओआरएस. वी.पी. सी. कक्कड़ (2003) 4 एससीसी 364:
[2003] 1 एस. सी. आर. 1034-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील की अधिकारिता 2012 की सिविल अपील सं. 2518।2006 के डब्ल्यू. ए. नं. 3 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांकित 07.01.2009 के निर्णय और आदेश से।

742

/

[2023] 12 एस सी आर।

रूप:

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कपूर, सूर्य प्रकाश, अर्जुन भाटिया, सुश्री दीपिका कालिया, केशव खंडेलवाल, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

जितेंद्र भारती, दीपक गोयल, मिथलेश कुमार जैसवाल, सुश्री अलका गोयल, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय करोल, जे।

तत्काल सूची इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए दो प्रश्न प्रस्तुत करती है। वे हैं -

(क) क्या 10 अप्रैल 2002 के समझौता ज्ञापन का खंड 4 विभागीय कार्यवाही जारी रखने पर रोक लगाता है जब उसके अधीन व्यक्ति पर उसी मूल के अपराधों के लिए आपराधिक न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जा रहा है?

(ख) क्या कुछ संबंधित कार्यवाहियों में बरी होने से बची हुई कार्यवाहियों में लाभ होता है? इसके अलावा, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में स्वचालित निर्वहन के अपराधी कर्मचारी पर अधिकार सुनिश्चित करना?

यह अपील, विशेष अनुमति के माध्यम से, रिट अपील No.03/2006 में पारित 7 जनवरी 2009 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके द्वारा 25 जुलाई 2005 की रिट याचिका (सिविल) No.12 में पारित आदेश में 28 मार्च 2003 के बैंक सेवाओं से बर्खास्तगी के आदेश और 16 अगस्त 2004 के आदेश के माध्यम से विभागीय अपील की अस्वीकृति के खिलाफ प्रतिवादी की अपील को अनुमति दी गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को अनुज्ञात कर लिया गया था।

पृष्ठभूमि

3. तत्काल विवाद के तथ्य जो रिकॉर्ड से निकलते हैं, वे हैं:- 3.1 प्रतिवादी पी. जादेगा 1 स्टेट बैंक में कार्यरत था।

1 इसके बाद "अपराधी कर्मचारी" के रूप में संदर्भित किया जाता है

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम पी. ज़डेगा

743

[संजय करोल, जे।]

दारपुई शाखा, आइजोल में सहायक (कैट) के रूप में भारत 2.तीन सरकारी खुदरा विक्रेताओं ने आइजोल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उक्त शाखा में उनके चालान-जमा नकद रसीद स्कॉल में दर्ज नहीं किए गए थे। जिला नागरिक आपूर्ति कार्यालय, आइजोल पश्चिम ने भी शिकायत दर्ज कराई कि एक खुदरा विक्रेता ने नकली चालान का उपयोग करके विशेष खाद्य पदार्थों की डिलीवरी ली थी। 3.2 इसके अनुसार, प्रत्यर्थी के खिलाफ 8 दिसंबर 1999 को एक ज्ञापन जारी करने के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसे 19 अप्रैल, 1996 को जमा के लिए Rs.61,908 प्राप्त हुआ था,

जिसके संबंध में चालान जारी किया गया था, लेकिन राशि कभी भी संबंधित खाते में जमा नहीं की गई थी। 21 फरवरी 1995 को Rs.24,640 और Rs.27,412 के संबंध में इसी तरह की दो अन्य घटनाओं का भी आरोप लगाया गया था।

3.3 उसके खिलाफ तीन अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गईं, जिसके अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस ज्ञापन के लिए अपने लिखित कारण दिखाने में, अपराधी कर्मचारी ने तर्क दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही को या तो हटा दिया जाना चाहिए या बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आपराधिक मामले लंबित थे, जो लेनदेन के एक ही सेट से उत्पन्न हुए थे।

3.4 अपीलार्थी-बैंक एक जाँच अधिकारी नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ा, जिसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि चार में से तीन आरोप स्थापित हो गए हैं। अपराधी कर्मचारी ने फिर से आरोपों से इनकार करते हुए, उस पर एक जवाब दायर किया, लेकिन अंततः 28 मार्च 2003 के बर्खास्तगी के आदेश के अनुसार, बैंक में सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया। सुनवाई के उचित अवसर के बाद उनके द्वारा दायर विभागीय अपील को 16 अगस्त 2004 को खारिज कर दिया गया था। 4. विभागीय अपील खारिज होने से व्यथित अपराधी कर्मचारी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की रिट याचिका (सिविल) No.12 दायर की। उक्त न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था: क्या, 10 अप्रैल के समझौता ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए

2 इसके बाद, "अपीलार्थी बैंक"

744

/

[2023] 12 एस सी आर।

2002 3 , अपराधी कर्मचारी (प्रत्यर्थी) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए थी या नहीं।

5. उक्त राज्य मंत्री के हस्ताक्षर के बाद, देसाई पुरस्कार द्वारा प्रदत्त शास्त्री पुरस्कार "सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में नहीं रहा", यह दर्ज करने के बाद न्यायालय ने कहा कि उक्त दस्तावेज का खंड 4 स्पष्ट और स्पष्ट था और इसलिए, बैंक के लिए आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन करना सही नहीं था।

6. हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए किसी न किसी तरह से अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामलों के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद राज्य मंत्री के खंडों के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से असंतुष्ट, 2006 की No.03 वाली एक रिट अपील दायर की गई थी। मामले की पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के बाद, खंड पीठ ने शास्त्री पुरस्कार की

प्रयोज्यता के संबंध में बैंक की ओर से विवाद पर चर्चा की और कहा कि आपराधिक मामलों के लंबित रहने के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखना एक उल्लंघन होगा, जिसे पैरा 521 (3) में दिया गया है।

8. अंत में, खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा और अनुशासनात्मक कार्यवाही अपास्त करते हुए करने का निर्णय लिया।

वर्तमान अपील

9. हमने अपीलकर्ता बैंक के वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह और अपराधी कर्मचारी के लिए श्री जितेंद्र भारती को सुना है। 10. इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों पर ध्यान आकर्षित करते हुए, अपीलकर्ता-बैंक की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि (i) आपराधिक मुकदमे को बाध्य करने वाली विभागीय कार्यवाही की शुरुआत एक स्वचालित रोक के बराबर नहीं होगी जब तक कि, निश्चित रूप से, मामले में विधि का एक जटिल प्रश्न शामिल न हो; (ii) उसी आक्षेपित कार्रवाई के संबंध में आपराधिक मुकदमे में बरी होने से नियोक्ता को विभागीय कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोका जाएगा;

3 इसके बाद "एम. ओ. एस." के रूप में संदर्भित किया गया: भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 52 'ए' श्रेणी के बैंकों के प्रबंधन और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ, भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उनके कर्मचारियों के बीच।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम पी. ज़डेगा

745

[संजय करोल, जे।]

और (iii) तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, द्विदलीय समझौते के प्रावधानों का केवल गैर-अनुपालन करने के परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू से ही अमान्य नहीं होगी। 11. दूसरी ओर, अपराधी कर्मचारी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही, तत्काल लीज का विषय, द्विदलीय समझौते का घोर उल्लंघन था, जिसे विधि का बल माना गया है। किसी भी मामले में, प्रतिवादी तीन आपराधिक मुकदमों में से दो में बरी हो जाता है। इसके अलावा, नियोक्ता द्वारा शुरू की गई कार्रवाई में देरी की गई और केवल अपराधी कर्मचारी को परेशान करने के लिए विचार किया गया।

12. हाथ में मुद्दे के गुण-दोष पर आगे बढ़ने से पहले, 10 अप्रैल 2002 के एम. ओ. एस. के खंड 4 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस विवाद में विवाद का मूल है, क्योंकि अपराधी कर्मचारी अनुशासनात्मक जांच के साथ कार्यवाही पर एक स्पष्ट प्रतिबंध का तर्क देता है जब समान लेनदेन से उत्पन्न आपराधिक मामले लंबित होते हैं, और अपीलकर्ता-बैंक इसके विपरीत प्रस्तुत करता है कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। खंड 4 निम्नानुसार है:-

“यदि किसी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने या उस पर मुकदमा चलाने के लिए कदम उठाए जाने के बाद, उसे ऑफिस के कमीशन के एक साल के भीतर मुकदमा नहीं चलाया जाता है, तो प्रबंधन उसके साथ ऐसे व्यवहार कर सकता है जैसे कि उसने "घोर दुराचार" या "मामूली कदाचार" का कोई कार्य किया हो, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है; बशर्ते कि यदि वह प्राधिकरण जो अभियोजन कार्यवाही शुरू करने वाला था, ऐसा करने से इनकार करता है या इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन के लिए कोई मामला नहीं है, तो प्रबंधन के लिए कर्मचारी के खिलाफ निर्वहन से संबंधित खंड 11 और 12 में नीचे दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत आगे बढ़ने के लिए खुला होगा, लेकिन वह निर्वहन से संबंधित खंड 11 और 12 में नीचे दिए गए उल्लंघन से बाहर होगा, लेकिन वह इस अवधि के दौरान कर्तव्य पर था। यदि प्रबंधन, पूछताछ के बाद, उसे सेवा में जारी नहीं रखने का निर्णय लेता है, तो वह केवल तीन महीने के वेतन और नोटिस के बदले में भत्तों के साथ समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि उपरोक्त खंड 3 में प्रदान किया गया है। यदि इस प्रकार स्थापित कार्यवाहियों की लंबितता के भीतर मुकदमा चलाया जाता है, तो ऐसी कार्यवाहियों को मुकदमे के पूरा होने तक रोक दिया जाएगा, जिसके बाद उपरोक्त खंड 3 में उल्लिखित प्रावधान लागू होंगे। ”

(जोर दिया गया)

746

/

[2023] 12 एस सी आर।

13. खंड 4 की व्याख्या के संबंध में, हम इस न्यायालय को

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य में देखा गया है। नीलम नाग 4 इस प्रकार है:-

“21. खंड 4 की सरल भाषा में, हमारी राय में, यह संस्था को प्रतिबंधित करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही को जारी रखने के लिए एक शर्त नहीं है, बहुत कम अनिश्चित रूप से, केवल अपराधी कर्मचारी के खिलाफ एक आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण। दूसरी ओर, यह संस्था को अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने वाला एक सक्षम प्रावधान है, यदि कर्मचारी पर अपराध करने के एक साल के भीतर अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाता है या अभियोजन पक्ष किसी भी सामग्री के अभाव में उसके खिलाफ आगे बढ़ने में विफल रहता है। 22. जैसा कि खंड 4 के अंतिम वाक्य से निकाला जा सकता है, जो उस मामले पर लागू होता है जहां आपराधिक मामला वास्तव में, जैसा कि इस मामले में, मुकदमे के लिए आगे बढ़ा है। “मुकदमे का पूरा होना” शब्द को एक उचित समय-सीमा के भीतर मुकदमे के पूरा होने के रूप में माना जाना चाहिए। यह खंड अपराधी कर्मचारी की सहायता के लिए नहीं आ सकता है-जिसे आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है और इससे भी अधिक मुकदमे को बढ़ाने के लिए पक्षकार है। ”

14. इस पृष्ठभूमि में, यह भी आवश्यक है कि हम समान मूल की दो कार्यवाहियों को एक साथ जारी रखने के संबंध में विधि की स्थिति पर गौर करें।

14.1 राजस्थान राज्य बनाम बी. के. मीणा और अन्य में यह न्यायालय । 5.

अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक के पहलू पर कुछ निर्णयों का उल्लेख किया और कहा:-

“14. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होगा कि उनमें से प्रत्येक इस निर्विवाद प्रस्ताव के साथ शुरू होता है कि दोनों कार्यवाहियों को एक साथ चलाने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है और फिर कहता है कि कुछ स्थितियों में, अनुशासनात्मक जांच के साथ आगे बढ़ना 'वांछनीय', 'उचित' या 'उचित' नहीं हो सकता है जब कोई आपराधिक मामला समान आरोपों पर लंबित हो। इस बात पर जोर दिया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना एक ऐसा मामला है जिसे किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए और कोई भी कठोर और तेज़ नियम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

4 (2016) 9 एससीसी 491 5 (1996) 6 एससीसी 417 747

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम पी. ज़डेगा

[संजय करोल, जे.] 748

इस बात में स्पष्ट किया जाए कि अपराधी अधिकारी का हित भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के त्वरित निष्कर्ष में निहित है। यदि वह आरोपों का दोषी नहीं है, तो उसके सम्मान को जल्द से जल्द सही ठहराया जाना चाहिए और यदि वह दोषी है, तो उससे विधि के अनुसार तुरंत निपटा जाना चाहिए। यह प्रशासन के हित में भी नहीं है कि गंभीर दुराचार के आरोपी व्यक्तियों को अनिश्चित काल के लिए, यानी आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा में लंबे समय तक जारी रखा जाना चाहिए। यह प्रशासन के हित में नहीं है। यह केवल दोषियों और बेईमानों के हितों की पूर्ति करता है। यद्यपि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न कारकों की गणना करना संभव नहीं है, लेकिन हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर जोर देना आवश्यक पाया कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को लंबे समय तक लंबित आपराधिक कार्यवाहियों के लिए रोक दिया जा रहा है। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक निश्चित रूप से एक मामला नहीं हो सकता है और न ही होना चाहिए।...

(बल दिया गया)

14.2 इसके अलावा, एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस मामले में यह न्यायालय लिमिटेड 6 ने विभागीय और आपराधिक कार्यवाही से एक साथ निपटने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट किया:-

ए। दोनों कार्यवाहियों को एक साथ जारी रखने पर कोई रोक नहीं है, हालांकि एक उपयुक्त, अलग मंच पर।

बी। यदि उक्त कार्यवाही समान/समान तथ्यों पर है और यदि अपराधी कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, तो यह वांछनीय होगा यदि विभागीय कार्यवाही को दूसरे के समापन तक रोक दिया जाए।

ग. आरोप की प्रकृति या विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों की संलिप्तता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, अर्थात्, शुरू किए गए मामले की प्रकृति, साक्ष्य और एकत्र की गई सामग्री।

घ. उपर्युक्त कारकों पर केवल विचार करना विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने का कारण नहीं हो सकता है।

6 (1999) 3 एस. सी. 679

/

[2023] 12 एस सी आर।

ई. यह याद रखना चाहिए कि विभागीय कार्यवाही में अनुचित और अन्यायपूर्ण रूप से देरी नहीं की जा सकती है।

च. यदि आपराधिक कार्यवाही में देरी होती है, तो दूसरे को, उसके कारण रोक दिए जाने के बाद, इसे जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप दो संभावनाएँ हो सकती हैं: या तो अपराधी कर्मचारी की स्थिति की पुष्टि या वह दोषी पाया जाता है, जिससे विभाग संबंधित उसे बाहर दिखाने में सक्षम होता है।

14.3 एम. पॉल एंथनी (ऊपर) में लिए गए दृष्टिकोण का उल्लेख इसके द्वारा किया गया था।

कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम में न्यायालय ।लिमिटेड वी.सी. नागराजू 7.

15. जैसा कि ऊपर उल्लिखित न्यायिक घोषणाओं से स्पष्ट है, यह वांछनीय हो सकता है या, कुछ परिस्थितियों में, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने की सलाह दी जा सकती है जब आपराधिक कार्यवाही चल रही हो; हालाँकि, रोक "निश्चित रूप से एक मामला" नहीं है और केवल सभी कारकों के पक्ष और विपक्ष पर विचार करने के बाद दी जानी है।

16. नीलम नाग (उपर्युक्त) को ध्यान में रखते हुए, खंड 4 के संचालन के लिए निम्नलिखित अनिवार्यताओं को निकाला जा सकता है -

ए। अपराधी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के प्रयासों को कम से कम एक साल बीत जाना चाहिए था।

बी। यदि ऐसा समय बीतने के बाद कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जाता है, तो विभाग अनुशासनात्मक कार्यवाई के लिए अपनी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ सकता है।

ग. यदि अभियोजन पक्ष बाद में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करता है, तो बाद वाले पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। ऐसी कार्यवाहियों पर केवल एक उचित अवधि के लिए रोक लगाई जानी चाहिए, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारण का विषय है। 17. अगला पहलू जिस पर हमें विचार करना चाहिए वह यह है कि क्या एक कार्यवाही में बरी होने पर दूसरे में बरी होना आवश्यक है।

17.1 नेल्सन मोटीस बनाम भारत संघ **8** में यह देखा गया था कि

प्रश्न यह है कि क्या विभागीय कार्यवाही जारी रह सकती थी

7 (2019) 10 एससीसी 367 8 (1992) 4 एससीसी 711 749

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम पी. ज़डेगा

[संजय करोल, जे.] **750**

आपराधिक कार्यवाहियों में बरी होने की स्थिति में कोई बल नहीं था क्योंकि "आपराधिक मामले की प्रकृति और दायरा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही से बहुत अलग है और इसलिए बरी करने का आदेश विभागीय कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकता है। "

17.2 सी. नागराजू (ऊपर) में यह देखा गया था:

"9. आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से नियोक्ता को नियमों और विनियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही करने की शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोका जा सकेगा। आपराधिक और विभागीय दोनों कार्यवाहियां पूरी तरह से अलग-अलग हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। [अजीत कुमार नाग बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, (2005) 7 एस. सी. सी. **764**] अनुशासनात्मक कार्यवाही में, प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी ऐसे आचरण का दोषी है जो उसे सेवा से हटाने के योग्य है या कम सजा, जैसा भी मामला हो, जबकि आपराधिक कार्यवाही में, प्रश्न यह है कि क्या पी. सी. अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ दर्ज अपराध स्थापित हैं, और यदि स्थापित हो जाता है, तो उस पर क्या सजा दी जानी चाहिए। सबूत का मानक, जांच का तरीका और दोनों मामलों में जांच और मुकदमे को नियंत्रित करने वाले नियम स्पष्ट रूप से अलग और अलग हैं। [राजस्थान राज्य बनाम बी. के. मीना, (1996) 6 एस. सी. सी. **417**]

(जोर दिया गया) **17.3** इस अवलोकन को कर्नाटक राज्य में प्रोफीट के साथ उद्धृत किया गया था।

वी. उमेश।/

18. यह रिकॉर्ड की बात है कि प्रश्न घटना (ओं) के संबंध में, प्राथमिकी 1996 में किसी समय दर्ज की गई थी, और अनुशासनात्मक कार्यवाही 8 दिसंबर 1999 को शुरू की गई थी। वर्ष 2002 में इसके पूरा होने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों सहित अनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली औपचारिकताओं को आगे पूरा करने के अनुसरण में, अपराधी कर्मचारी को 28 मार्च 2003 के आदेश के पारित होने के साथ सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

19. अपराधी कर्मचारी द्वारा दायर एक अपील को भी 2004 में खारिज कर दिया गया था। यह अनुशासन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही है।

9 (2022) 6 एस. सी. सी. 563

/

[2023] 12 एस सी आर।

यह कार्यवाही कि अपराधी कर्मचारी ने फरवरी 2005 में, राज्य मंत्री के खंड 4 पर भरोसा करने की मांग करते हुए, इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका का नेतृत्व किया, जो हमारे विचार से, केवल इसके कार्यान्वयन को रोकने के लिए एक विलंबित प्रयास था। 20. हम नीलम नाग (उपरोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को दोहराते हैं कि मुकदमे के पूरा होने को "उचित समय सीमा के भीतर" पूरा किया जाना चाहिए और यह कि खंड कर्मचारी की सहायता के लिए "अधिक नहीं", "मुकदमे को बढ़ाने" के लिए नहीं आ सकता है। तत्काल मामले में, वर्ष 1996 में दर्ज अपराध से संबंधित मुकदमे का पूरा होना कहीं भी पूरा होने के करीब नहीं है।

21. विधि के एक सिद्धांत के रूप में, हम पहले ही देख चुके हैं कि आपराधिक मुकदमे के लंबित एक विभागीय कार्यवाही एक स्वचालित रोक की गारंटी नहीं देगी जब तक कि, निश्चित रूप से, विधि का एक जटिल प्रश्न शामिल न हो। इसके अलावा, किसी आपराधिक मामले में वस्तुतः बरी होना किसी अपराधी कर्मचारी के पक्ष में कार्यवाही को बंद करने या समाप्त करने के समान नहीं होगा।

22. जांच की कार्यवाही शुरू करने पर अपराधी कर्मचारी की प्रतिक्रिया को देखने के बाद, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखते हैं कि एम. ओ. एस. की कोई याचिका कभी नहीं ली गई थी। आपराधिक मुकदमे के समापन की प्रतीक्षा में अनुशासनात्मक कार्यवाही को स्थगित करने का कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया था।

23. यह देखा गया है कि अधिकारी ने न तो दलील दी और न ही आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या दोनों कार्यवाही को एक साथ जारी रखने के परिणामस्वरूप उसके प्रति हुए पूर्वाग्रह का संकेत दिया।

24. उपरोक्त सभी सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हम यह मानते हैं कि न तो यह अपराधी कर्मचारी का मामला था कि जिस मुकदमे के अधीन उसे अपराध करने के एक वर्ष

के भीतर शुरू किया गया था और न ही रिकॉर्ड इस आशय की बात करता है। यह जांच रिपोर्ट 10, दिनांक 3 दिसंबर 2001 में है कि एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान की जा रही अनुशासनात्मक कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज की गई है, लेकिन वहां भी, कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की गई है।

25. इसके अलावा, यह अपराधी कर्मचारी का मामला नहीं है कि बैंक की अनुशासनात्मक कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था।

10 पेपरबुक 751 का अनुलग्नक पी-4 Pg.109

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम पी. ज़डेगा

[संजय करोल, जे.] 752

26. इन दोनों पहलुओं को इस तथ्य के साथ लिया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना अनिवार्य नहीं है, विशेष रूप से जब वे एक वर्ष की निर्धारित अवधि के बाद शुरू की गई हैं, तो हम नीचे दी गई अदालतों से सहमत नहीं हो सकते हैं। खंड 4 के भीतर प्रतिबंध पूर्ण नहीं है और तथ्यों पर लागू किया जाना है। ऐसी स्थिति में, डिवीजन बेंच की

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और अन्य पर निर्भरता। पी. सी. कक्कड़, **11** पूरी तरह से

गलत धारणा है। रिट अपील में उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष के विपरीत, कक्कड़ (उपरोक्त) अपीलार्थी-बैंक की स्थिति को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, "आपराधिक मामले में बरी होना कदाचार या अन्यथा करने का निर्धारक नहीं है, और आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद, अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए खुला है। "27. आश्चर्य की बात है कि कक्कर (ऊपर) का उल्लेख करने के बाद, जो उपरोक्त स्थिति लेता है, उच्च न्यायालय, अगले ही पैराग्राफ में, बिना किसी तर्क के, बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण रखता है। वास्तव में, हम यह दोहराने के लिए कक्कड़ (उपरोक्त) का उल्लेख कर सकते हैं कि बैंक में कार्यरत व्यक्तियों से क्या अपेक्षित है, जबकि यह भी देखते हुए कि इसमें अपराधी कर्मचारी का आचरण इन सिद्धांतों के विपरीत है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की:-

"14. ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों का प्रयोग करने के लिए एक बैंक अधिकारी की आवश्यकता होती है। वह जमाकर्ताओं और ग्राहकों के पैसे का सौदा करता है। बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को बैंक के हितों की रक्षा करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, ईमानदारी, समर्पण और परिश्रम के साथ करने के लिए हर संभव कदम उठाने की आवश्यकता है और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो बैंक अधिकारी के लिए अनुचित हो। अच्छे आचरण और अनुशासन बैंक के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के कामकाज से अविभाज्य हैं। एक संगठन का अनुशासन विशेष रूप से एक बैंक अपने प्रत्येक अधिकारी और अधिकारी पर निर्भर करता है जो अपने आवंटित क्षेत्र के भीतर काम करते हैं और काम करते हैं। अपने अधिकार से परे काम करना अपने आप में अनुशासन का उल्लंघन है और एक दुराचार है।" (जोर

दिया गया) 28.पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए और ऊपर चर्चा की गई न्यायिक घोषणाओं के आलोक में, अपील सफल होती है।हम रिट अपील में पारित 7 जनवरी 2009 के निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं।

11 (2003) 4 एस. सी. सी. 364

/

[2023] 12 एस सी आर।

No.03/2006, और परिणामस्वरूप, 2005 की रिट याचिका (सिविल) No.12 दिनांक 25 जुलाई 2005 में आदेश पारित किया गया।

29. इस अपील अंतर्गत प्रस्तुत प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:29.1 दिनांक 10 अप्रैल 2002 के राज्य मंत्री के खंड 4 में आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने के परिणामस्वरूप विभागीय कार्यवाही के पूर्ण ठहराव की परिकल्पना नहीं की गई है।विधि की स्थिति यह है कि उत्तरार्द्ध का ठहराव वांछनीय है, लेकिन इसे केवल एक उचित अवधि के लिए लागू किया जाना है।

29.2 कार्यवाहियों की प्रकृति पूरी तरह से अलग और विशिष्ट होने के कारण, आपराधिक कार्यवाहियों में बरी होने से अपराधी कर्मचारी को बाद में किसी भी लाभ या विभागीय कार्यवाहियों में स्वचालित निर्वहन का अधिकार नहीं मिलता है।

30. नतीजतन, 28 मार्च 2003 (D.P.S.No.2003/02) के ज्ञापन के अनुसार श्री पी. जादेंगा की सेवा से बर्खास्तगी को बहाल कर दिया गया है।31. वार्ताकार आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

32. दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

दिव्या पांडे